



Essay on Pradhan Mantri Mudra Yojana

Key Points

1. Introduction

- 1) MUDRA or Micro Units Development Refinance Agency Scheme was launched on 8th April 2015. The objective of this scheme is to support the entrepreneurs of MSME sector.
- 2) This Bank would be responsible for **regulating and refinancing all Micro-Finance Institutions (MFI)** which are in the business of lending to micro/small business entities engaged in **manufacturing, trading and services activities**.
- 3) Micro-finance is an important tool in an economy like India where a million new workers are added to workforce every month especially in small businesses.
- 4) NSSO Survey 2013 suggests that there are 5.77 crore small businesses like manufacturing, trading or services.

2. Body

- 1) **-Shishu:** covering loans upto Rs. 50,000/-
-Kishor: covering loans above Rs. 50,000/- and upto Rs. 5 lakh
- Tarun: covering loans above Rs. 5 lakh and upto Rs. 10 lakh
- 2) These loans are given by Commercial Banks, RRBs, Small Finance Banks, Cooperative Banks, MFIs and NBFCs.
- 3) Frame policy guidelines for micro/small enterprise MFIs (Micro Finance Institutions), Registration of MFIs, Regulation of MFIs, Promoting right technology solutions for problems faced by MFIs and borrowers, Supporting **financial literacy**.
- 4) Ex- Bharat Finance, Ujjivan Finance, Equitas etc.
- 5) Small entrepreneurs employ 12 crore people and face problems in getting financial assistance.
- 6) More than 2.2 lakh crore loan has been disbursed so far (2017-18)
- 7) Problems – Financial literacy, Fraud, Delay in processing, bank NPA.

3. Conclusion

- 1) Micro Finance is a potent tool for development of economy, enhancing opportunity for income generation in India.
- 2) Provision for checking NPA.
- 3) Very crucial for economic growth and job creation.
- 4) This also promotes a rewarding entrepreneurial ecosystem.
- 5) This is correct step towards a sustainable economy.

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना पर निबंध

1. Introduction

- 1) मुद्रा या माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनंस एजेंसी योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी।
- 2) इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों को समर्थन देना है।
- 3) यह बैंक सभी सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) को विनियमन और पुनर्वित्त करने के लिए जिम्मेदार होगा जो विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं की गतिविधियों में लगे सूक्ष्म / लघु व्यवसायिक संस्थाओं के लिए ऋण देते हैं।
- 4) भारत जैसे अर्थव्यवस्था में माइक्रो-फायनेंस एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जहां हर महीने विशेषकर छोटे व्यवसायों में लाखों नए कर्मचारी कार्यबलियों में शामिल होते हैं।
- 5) एनएसएसओ सर्वेक्षण 2013 ने बताया कि निर्माण, व्यापार या सेवाओं जैसे 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय हैं।

2. Body

- 1) शिशु: ऋण - ₹ 50,000 तक - किशोर: 50,000 रुपये से ₹ 5 लाख तक - तरुण : ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक

- 2) ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए गए हैं।
- 3) माइक्रो / छोटे उद्यम एमएफआई (माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशंस), एमएफआई का पंजीकरण, एमएफआई का विनियमन, एमएफआई और उधारकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं के लिए सही प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए फ्रेम नीतिगत दिशानिर्देश, वित्तीय साक्षरता का समर्थन करना।
- 4) लघु उद्यम 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं
- 5) वित्तीय सहायता प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं।
- 6) अभी तक 2.2 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है (2017-18)
- 7) समस्याएं - वित्तीय साक्षरता, धोखाधड़ी, प्रसंस्करण में देरी, बैंक एनपीए

3. Conclusion

- 1) माइक्रो फाइनेंस अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो भारत में आय पैदा करने का अवसर बढ़ाता है।
- 2) एनपीए की जांच के लिए प्रावधान
- 3) आर्थिक विकास और नौकरी सृजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- 4) यह एक स्थायी अर्थव्यवस्था की दिशा में सही कदम है